PCSMANTRA.COM

सच्चर रिपोर्ट के 20 वर्ष: समावेशन को आंकड़ों से कैसे परखें?

समाचार-संदर्भ: 2026-11-17 | **प्रकाशन:** 17 नवंबर 2026
मुख्य परीक्षा: GS-II: सामाजिक न्याय और समावेशन
प्रिलिम्स: अवधारणाएं और कथन-आधारित अभ्यास



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

यह भी पढ़ें: महिलाओं की श्रम-भागीदारी: अवैतनिक देखभाल कार्य की दीवार और डेटा की तलाश

खबरों में क्यों

17 नवंबर 2026 को सच्चर समिति की रिपोर्ट सौंपे जाने के 20 वर्ष पूरे हुए। रिपोर्ट 17 नवंबर 2006 को सरकार को दी गई थी और 30 नवंबर 2006 को संसद के दोनों सदनों में रखी गई थी। इस अवसर पर मुख्य प्रश्न है कि सामाजिक समावेशन के लिए विश्वसनीय आंकड़ों और परिणाम-आधारित समीक्षा का उपयोग कैसे हो।

समिति का उद्देश्य

प्रधानमंत्री कार्यालय ने 9 मार्च 2005 को न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति बनाई थी। उसका विषय भारत के मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन था। यह पूरे अल्पसंख्यक समुदायों के हर मुद्दे पर सामान्य आयोग नहीं था।

समिति ने शिक्षा, रोजगार, आर्थिक अवसरों, बैंकिंग तथा बुनियादी सुविधाओं से संबंधित जानकारी का अध्ययन किया। इसलिए इसे केवल आरक्षण संबंधी बहस तक सीमित कर देना उसके व्यापक विकास-संदर्भ को कम कर देता है।

रिपोर्ट की पद्धतिगत सीख

धारणा के बजाय प्रमाण: किसी समुदाय की स्थिति पर निष्कर्ष शिक्षा, काम और सेवाओं तक पहुंच के आंकड़ों से निकाले जाएं।

औसत से आगे: राष्ट्रीय औसत के साथ समूहों और क्षेत्रों के अंतर को भी देखा जाए।

बाधा की पहचान: कम उपलब्धि दर्ज करना पहला चरण है। यह समझना भी जरूरी है कि कारण स्कूल की दूरी, ऋण तक पहुंच, कौशल या अवसरों की कमी में कहां है।

सरकार की ऐतिहासिक अनुवर्ती कार्रवाई

31 अगस्त 2007 के संसदीय वक्तव्य में शिक्षा की पहुंच, कौशल, बैंक ऋण और बुनियादी सुविधाओं पर कदम प्रस्तावित किए गए थे। इसमें राष्ट्रीय डेटा बैंक तथा आकलन एवं निगरानी व्यवस्था का उल्लेख भी था।

यह उस समय की सरकारी कार्ययोजना थी। इसे 2026 में हर प्रस्ताव पूरी तरह लागू हो जाने या वर्तमान परिणाम सुधर जाने का प्रमाण नहीं माना जा सकता। उसी तरह 2006 की साक्षरता या रोजगार की संख्या को आज का आंकड़ा नहीं लिखना चाहिए।

आज समीक्षा कैसे हो?

समय-संगत डेटा: नए आंकड़े उसी परिभाषा और तुलनीय समूहों के साथ पढ़े जाएं।

घोषणा बनाम परिणाम: धन आवंटन, खर्च और वास्तविक शैक्षणिक अथवा आर्थिक नतीजे अलग संकेतक हैं।

स्थानीय जरूरत: लड़कियों की शिक्षा, कौशल और ऋण-सुविधा जैसी बाधाओं की क्षेत्र-विशेष पहचान हो।

जवाबदेही: प्रगति का नियमित और सार्वजनिक आकलन हो, लेकिन व्यक्ति की संवेदनशील जानकारी की रक्षा भी हो।

आगे की राह

सच्चर रिपोर्ट की स्थायी सीख किसी पुराने प्रतिशत को दोहराना नहीं, बल्कि विकास के अंतर को प्रमाण के आधार पर पहचानना है। समावेशन की नीति को न केवल योजनाओं की संख्या, बल्कि अवसर और परिणाम के अंतर में बदलाव से परखना चाहिए।

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. सच्चर समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: इसका गठन 2005 में किया गया था।

कथन 2: इसका विषय भारत के मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति था।

कथन 3: इसकी रिपोर्ट पहली बार 2026 में संसद में रखी गई।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

▼ उत्तर और व्याख्या

सही उत्तर: (a)

कथन 1 सही है। गठन 9 मार्च 2005 को हुआ था।

कथन 2 सही है। यही समिति का निर्धारित विषय था।

कथन 3 गलत है। रिपोर्ट 30 नवंबर 2006 को दोनों सदनों में रखी गई थी।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

सामाजिक समावेशन की नीति में समूह-विशिष्ट आंकड़े और परिणाम-आधारित मूल्यांकन क्यों आवश्यक हैं? सच्चर समिति के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (150 शब्द) (10 अंक)

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: समिति का संदर्भ

मुख्य भाग में: औसत के पीछे अंतर; शिक्षा-रोजगार-ऋण बाधाएं; पुराने और नए आंकड़ों की तुलनीयता

निष्कर्ष में: पारदर्शी समीक्षा और निजता।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

सच्चर समिति ने मुस्लिम समुदाय की विकास-संबंधी स्थिति का अध्ययन किया। उसके 20 वर्ष पूरे होने पर पुराने आंकड़ों को वर्तमान बताने के बजाय नई, तुलनीय समीक्षा जरूरी है।

समिति का गठन कब हुआ?

9 मार्च 2005 को।

रिपोर्ट कब सौंपी और संसद में रखी गई?

17 नवंबर 2006 को सौंपी गई; 30 नवंबर 2006 को दोनों सदनों में रखी गई।

क्या 2006 के निष्कर्ष आज की स्थिति के आंकड़े हैं?

नहीं। वर्तमान स्थिति के लिए नए और तुलनीय साक्ष्य चाहिए।

POSMANTRA.COM

स्रोत

- www.minorityaffairs.gov.in
- www.minorityaffairs.gov.in